बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 77

निर्यात फिर कमजोर

देश के व्यापार संतुलन से संबंधित अप्रैल महीने के आधिकारिक आंकड़े जारी किए जा चुके हैं और ये बहुत परेशान करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की तरह अप्रैल में भी निर्यात में वृद्धि देखने को मिली लेकिन यह कतई उल्लेखनीय नहीं थी। 0.64 फीसदी की वृद्धि के साथ यह निर्यात में सालाना आधार पर इस वर्ष हुई सबसे धीमी वृद्धि थी। ये आंकड़े अपने आप में चिंता का विषय नहीं हैं, असली चिंता की बात यह है कि निर्यात में जो मामूली सुधार देखने को मिला था उसमें कोई स्थायित्व देखने को नहीं मिला है। इस बीच सोने का आयात सालाना आधार पर 54 फीसदी बढ़ा जबकि तेल आयात में सालाना आधार पर 9.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार कुल आयात में 4.5 फीसदी की बढ़ोतरी आई। इस बीच व्यापार घाटा 15.3 अरब डॉलर के साथ पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

अगर आंकड़ों पर और करीबी नजर डालें तो दो मोर्चों पर कुछ राहत भी नजर आती है। पहला, गैर तेल, गैर स्वर्ण आयात में कमी का सिलसिला जारी है। फरवरी 2019 में इनमें 1.9 फीसदी की कमी आई थी। मार्च 2019 में यह 2.7 फीसदी घटा और अप्रैल में भी यह 2.2 फीसदी कम हुआ। हालांकि यह अपने आप में बुरी खबर नहीं है लेकिन यह देश में कमजोर उपभोक्ता मांग को दर्शाती है जो चिंता की बात है। बीते कुछ वर्ष के दौरान देश की विकास गाथा काफी हद तक मजबूत उपभोक्ता मांग पर निर्भर रही है। गैर तेल, गैर स्वर्ण आयात समेत तमाम प्रमुख संकेतक यह दर्शाते हैं कि यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। तेल आयात में इजाफा दुनिया भर में तेल कीमतों में आ रहे बदलाव को भी दर्शाती है और अमेरिका तथा ईरान के बीच बढ़ते तनाव को भी। इस बीच निर्यात का ब्योरा और चिंतित करने वाला है।

समग्र रूप से भले ही निर्यात में इजाफा हुआ हो लेकिन गैर तेल निर्यात में 3.1 फीसदी की कमी आई है। इससे पता चलता है कि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में अचानक और तेज गिरावट आई है। दो महीनों की वृद्धि के बाद इसमें पहली बार गिरावट आई है। उम्मीद की गई थी कि शुरुआती वृद्धि कायम रहेगी लेकिन अप्रैल के आंकड़े सामने आने के बाद ऐसा लगता नहीं कि यह संभव होगा।

बहुत संभव है कि कमजोर घरेलू मांग वृद्धि के लिए अच्छी खबर न हो लेकिन इसका यह अर्थ भी है कि आने वाले महीनों में शायद बाहरी खाते को लेकर उतना अधिक चिंतित होने की आवश्यकता न हो। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वर्ष 2019 में चालू खाते का घाटा गिरकर सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 फीसदी के बराबर रहेगा। वर्ष 2018 में यह 2.4 फीसदी था। जाहिर है अगर तेल कीमतों में तेज उछाल आएगी तो बाकी अनुमान धरे रह जाएंगे। परंतु इन आंकड़ों से असल सबक यह मिलता है कि भारत का निर्यात, खासतौर पर इंजीनियरिंग वस्तुओं, कपड़े और रसायन का निर्यात तब तक नहीं सुधर सकता जब तक कि नीति निर्माता इस पर ध्यान नहीं देते। अब तक नीतियों का ध्यान टैरिफ नीति और आयात प्रतिस्थापन के जरिये आयात कम करने पर रहा है। हालांकि व्यापार घाटे के प्रबंधन का सबसे स्थायी तरीका निर्यात बढ़ाना है। इससे रोजगार भी पैदा होते हैं और घरेलू विनिर्माण की अतिरिक्त क्षमता की समस्या भी दूर होती है।

निर्यातकों ने वस्तु एवं सेवा कर के कारण उनकी कार्यशील पूंजी में कमी आने की जो शिकायतें दर्ज कराई हैं उनको हल करना आवश्यक है। अगली सरकार को भी लालफीताशाही तथा निर्यातकों को सीमा पर होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे।

बिनय सिन्हा

सर्वाधिक जनसंख्या वाले एशियाई देशों की प्रगति

	प्रति व्यक्ति जीडीपी		वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी (प्रतिशत, डॉलर)		जीडीपी में निर्यात का अनुपात		महिला श्रम भागीदारी (प्रतिशत)		मानव विकास सूचकांक वैल्यू		रैंक
देश	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1980	2,018	1980	2018	1980	2017	1990	2018	1990	2017	2017
बांग्लादेश	274.3	1,744.5	0.2	0.34	5.5	15	23.6	36	0.39	0.61	136
चीन	309.4	9,608.4	2.74	15.82	5.9	19.8	73.2	61.3	0.5	0.75	86
भारत	276.4	2,036.2	1.7	3.21	6.1	18.8	30.4	23.6	0.43	0.64	130
इंडोनेशिया	673.2	3,870.6	0.89	1.21	30.5	20.2	44.5	52.2	0.53	0.69	116
पाकिस्तान	384.9	1,555.4	0.28	0.37	12.5	8.2	14	23.9	0.4	0.56	150

स्रोत- आईएमएफ वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, विश्व बैंक, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट

बड़ी आबादी वाले 5 एशियाई देशों का लेखा-जोखा

चीन ने पिछले 40 वर्षों में हरेक पैमाने पर बाकी एशियाई देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान भारत और बांग्लादेश का प्रदर्शन भी सुधरा है। विस्तार से बता रहे हैं **शंकर आचार्य**

कभी-कभी भारत में तात्कालिक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों की गहमागहमी से दूर हट जाना और देशों के दीर्घकालिक विकास प्रदर्शन पर नजर डालना शिक्षाप्रद होता है। यह लेख एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच देशों के बारे में कुछ बुनियादी आंकड़ों और उससे जुड़ी टिप्पणियों को पेश करता है। ये देश हैं- चीन (139.5 करोड़), भारत (133.4 करोड़), इंडोनेशिया (26.4 करोड़), पाकिस्तान (20.1 करोड़) और बांग्लादेश (16.5 करोड़)। एक साथ इन पांचों देशों की आबादी वर्ष 2018 में दुनिया की कुल 7.46 अरब आबादी का 45 फीसदी रही। इनमें अकेले चीन और भारत का योगदान क्रमश: 18.7 फीसदी और 17.8 फीसदी है।

सारिणी के पहले दो कॉलम देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी को 1980 और 2018 के संदर्भ में दिखाते हैं। यह गौर करना दिलचस्प है कि इस पैमाने से 1980 में इंडोनेशिया सर्वाधिक समृद्ध या सबसे कम गरीब देश था और पाकिस्तान दूसरे, चीन तीसरे, भारत चौथे एवं बांग्लादेश अंतिम स्थान पर था। लेकिन 2018 में तस्वीर नाटकीय रूप से बदल चुकी थी। चीन में करीब 35 वर्षों तक अनवरत 8 फीसदी दर से प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी बढ़ने से उसकी प्रति व्यक्ति आय 30 गुना बढ़कर करीब 10,000 डॉलर हो गई। यह आंकड़ा दूसरे स्थान पर मौजूद इंडोनेशिया की तुलना में ढाई गुना और आखिरी पायदान पर खड़े पाकिस्तान से छह गुना अधिक है। इस असामान्य वृद्धि का कारण यह नहीं है कि बाकी चारों देशों की वृद्धि दर स्थिर बनी रही। इस दौरान उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि भी 1980 की तुलना में चार से आठ गुना तक बढ़ी है। दरअसल चीन जैसे विशाल एवं बड़ी आबादी वाले देश की विस्फोटक वृद्धि ऐतिहासिक रूप से असाधारण एवं अभूतपूर्व रही।

तीसरा और चौथा कॉलम दिखाता है कि इन देशों ने 38 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी किस तरह बढ़ाई है? वर्ष 1980 में इनकी हिस्सेदारी महज 5.8 फीसदी होती थी लेकिन 2018 में यह 21 फीसदी के सम्मानजनक स्तर पर पहुंच गया। अगर क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में गणना करें तो यह हिस्सेदारी 30 फीसदी के खुशनुमा स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहां फिर से चीन का ही दबदबा है जिसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 16 फीसदी की हिस्सेदारी दूसरे स्थान पर मौजूद भारत की पांच गुना है। अगर चीन को सूची से बाहर कर दें तो बाकी चार एशियाई देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 1980 के 3.1 फीसदी से मामूली बढ़त के साथ 2018 में 5.1 फीसदी तक ही पहुंच सकी।

इन 38 वर्षों में से अधिकांश समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था और उसके सहभागी देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पूंजी प्रवाह में हुए उदारीकरण से लाभ हो रहा था। सारिणी का पांचवां एवं छठा कॉलम 1980 के तीन सबसे गरीब देशों- चीन, भारत एवं बांग्लादेश की जीडीपी में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात खंड में हुई उच्च वृद्धि को रेखांकित करता है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में निर्यात हिस्सेदारी गिरने की बड़ी वजह तेल निर्यात में कमी और खराब नीतियों का क्रियान्वयन रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन, भारत एवं बांग्लादेश ने वैश्विक वस्तु निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। चीन का हिस्सा 1980 के महज 1 फीसदी से बढ़कर 2017 में करीब 13 फीसदी तक पहुंच चुका था। उस समय तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका था। इसी दौरान वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.4 फीसदी से चार गुना बढ़कर 1.7 फीसदी हो गई लेकिन इसके बावजूद यह 2018 में चीन की हिस्सेदारी का आठवां भाग ही है।

सारिणी के सातवें एवं आठवें कॉलम रोजगार परिदृश्य एवं मानव विकास के संदर्भ में 1990-2018 के दौरान महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) पर विश्व बैंक रिपोर्ट से जुटाए आंकड़े पेश करते हैं। यह संकेतक सामान्य रोजगार परिस्थितियों खासकर राष्ट्रीय श्रमशक्ति में महिलाओं पर रोशनी डालता है। वर्ष 1990 में चीन का एफएलएफपीआर 73 फीसदी के उच्च स्तर पर था जो भारत का करीब ढाई गुना था। हालांकि अगले 28 वर्षों में दोनों ही देशों का एफएलएफपीआर घटा है लेकिन आनुपातिक तौर पर चीन के पक्ष में अंतराल बढ़ गया। असल में, इस गिरावट के बावजूद चीन का एफएलएफपीआर वर्ष 2018 में इन पांचों देशों में सबसे अधिक रहा है। दुर्भाग्य से, वर्ष 2018 आते-आते भारत में एफएलएफपीआर इन देशों में सबसे कम रहा और बांग्लादेश एवं पाकिस्तान भी उससे बेहतर स्थिति में रहे।

सारिणी के आखिरी तीन कॉलम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के रुझानों को इंगित करते हैं। सबसे पहले 1990 में इस सूचकांक का इस्तेमाल महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने किया था। नौवां और दसवां कॉलम 1990 और 2017 में हरेक देश के एचडीआई के गणित मूल्यों को दर्शाते हैं जबकि आखिरी कॉलम 2017 में हरेक देश की रैंकिंग दिखाता है।

इन सभी आंकड़ों से कई दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। पहला और सबसे अहम, सभी पांचों जनसंख्या-बहुल देश 27 वर्षों में उनके एचडीआई मूल्यों में खासी बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। दूसरा, प्रतिशत बढ़ोतरी के मामले में बांग्लादेश (56 फीसदी) के साथ सबसे आगे रहा जिसके बाद चीन (50 फीसदी) और भारत (48 फीसदी) का स्थान रहा। तीसरा, 1990 में उच्च आधार मूल्य होने और अगले 27 वर्षों में तगड़ी प्रतिशत वृद्धि के चलते चीन 2017 की रैंकिंग में 86वें स्थान के साथ सबसे आगे रहा और इंडोनेशिया (116वां) एवं भारत (130वां) उसके पीछे रहे। पाकिस्तान तो 150वीं रैंकिंग के साथ इस सूची में सबसे पीछे रहा।

सवाल उठता है कि इन 40 वर्षों में एशिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के विकास संकेतकों के क्या निहितार्थ हैं? पहली बात यह है कि यह असल में चीन की कहानी है। प्रति व्यक्ति आय, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संपर्क और मानव विकास पैमानों में हुए बदलावों पर गौर करें तो चीन बाकी चारों देशों से सबसे आगे है। ऐसे में चीन का इस अवधि में एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरने से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, भारत, इंडोनेशिया एवं बांग्लादेश ने अधिकांश पैमानों पर काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है। यह दलील देना भी संभव है कि बांग्लादेश और भारत ने अधिकतर विश्लेषकों की उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। तीसरा, यह देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान अमूमन हरेक संकेतक में पिछड़ गया है और अब निचली पायदान पर है।

(लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

विश्वसनीयता ही संगठन को बनाती है संस्थान

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

यह लेख उच्चतम न्यायालय और विश्वसनीयता के मौजूदा संकट के केंद्र में मौजूद बिंदुओं के बारे में नहीं है। प्रैक्टिस करने वाला एक वकील होने के नाते ऐसे मसलों पर चर्चा करने को सही और गलत के गुण-दोषों पर टिप्पणी के तौर पर देखे जाने का भी जोखिम जुड़ा है जिसका न्यायिक समुदाय एवं संबद्ध पक्षों के हाथों गंभीर नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। सच तो यह है कि 'संकट' शब्द का इस्तेमाल भी एक भावनात्मक मुद्दा हो सकता है। इसके बजाय यह लेख संस्थानों और उन सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में है कि 'संगठन' किस तरह 'संस्थानों' में परिवर्तित होते हैं। जब कोई संगठन न्याय प्रदान करने की व्यवस्था के शीर्ष पर है तो उसे महज कानूनी व्याख्या से परे विश्वसनीयता की अघोषित जरूरत भी होती है। यह शीर्ष अदालत के फैसलों को मिलने वाली सामाजिक स्वीकृति के केंद्र में होता है।

संवैधानिक एवं विधिक तौर पर उच्चतम न्यायालय हमेशा सही होता है क्योंकि यह अंतिम न्यायालय है। यह हमेशा सही होने की वजह से अंतिम नहीं होता है। किसी भी संस्थान के निर्णय सही या गलत ठहराए जाने के लिए मुक्त हो सकते हैं। किसी भी विवाद को एक जगह जाकर खत्म होना होता है और वह रास्ता उच्चतम न्यायालय पर जाकर बंद हो जाता है। हालांकि किसी भी दूसरे संगठन की तरह इसका संचालन भी इंसान ही करते हैं। इंसान होने का बुनियादी गुण यह है कि वह गलती भी कर सकता है, हम गलतियां करने के आदी हैं और काफी गलत भी हो सकते हैं। लिहाजा सभी तरह के विवाद यहीं खत्म हो जाते हैं। समाज मान लेता है कि यह समापन केवल हमारे संविधान एवं मानव-निर्मित कानून के कहने से ही नहीं होता है बल्कि न्यायालय की मौलिक विश्वसनीयता के नाते इसके आचरण को समाज की स्वीकृति मिलने की वजह से भी होता है।

विश्वसनीयता ही किसी 'संगठन' को 'संस्थान' में परिवर्तित करती है। ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। ऐसे न्यायाधीश हैं जिनकी अदालतों से दावा ठुकराए जाने के बाद भी वादियों को यह संतोष रहता है कि उनकी बात अच्छी तरह सुनी गई है। वहीं कुछ ऐसे न्यायाधीश भी हैं जिनकी अदालतों से निकलते समय वादी को जीत मिलने के बाद भी किस्मत का साथ मिलने से राहत का भाव रहता है, न कि जीत का हकदार होने के नाते संतोष का भाव होता है। यह सब इसलिए होता है कि इस न्यायिक व्यवस्था को चलाने वाले इंसान ही होते हैं।

जहां भी इंसान काम करते हैं वहां विचारों में अंतर होगा। कहा-सुनी हो सकती है, स्वस्थ बहस हो सकती है। एक-दूसरे पर गलत काम करने के सही एवं गलत आरोप लगाए जा सकते हैं। मानव संसाधनों पर निर्णय लेने के तरीकों में गहरा अनौचित्य हो सकता है और यह किसी भी संगठन का आवश्यक गुण है। लेकिन संगठन में विचारों के अंतर से निपटने के तरीके, विवादों के समाधान के तरीके और आरोपों के निपटान के तरीके से ही यह परिभाषित किया जाता है कि कोई संगठन संस्थान बन पाया है या नहीं।

एक संस्थान के लिए दीर्घकालिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वह अपने लोगों और उसके पास आने वाले लोगों से कैसा बरताव करता है। मत भिन्नता को सेंसर कर देना या आवाज उठाने वाले को प्रताड़ित करना संस्थान में तब्दील नहीं हो पाए किसी भी संगठन के लिए आसान हो सकता है। लेकिन एक वास्तविक संस्थान असहमति, विचारों में भिन्नता को जगह देगा और उसके प्रति पारदर्शिता बरतेगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जिंसबर्ग और न्यायमूर्ति स्केलिया के विचार एक-दूसरे से काफी अलग थे- एक लिबरल तो दूसरे कंजर्वेटिव मत के थे। लेकिन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और अपने फैसलों से न्याय एवं कानून के प्रति अपने नजरिये में इस फर्क को जगह भी दी।

अब हमारे देश की एक और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का रुख करते हैं जिस पर समूची निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का दायित्व होता है। हमें अब मालूम है कि चुनाव आयोग के एक आयुक्त आयोग के हालिया फैसलों से असहमति जता चुके हैं लेकिन बाकी दो आयुक्त तकनीकी एवं आभासी तर्कों के आधार पर बहुमत से फैसले सुनाकर असहमति की इस आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। उनकी दलील यह है कि ये फैसले केवल प्रशासनिक प्रकृति के हैं।

सही एवं गलत को लेकर चुनाव आयोग के विचारों को चाहे जितने अलग रूप में देखा जाए लेकिन चुनावों के निर्विघ्न संचालन के लिए वे अहम हैं। चुनाव संपन्न होंगे और उसके नतीजे को मोटे तौर पर पूरा समाज मान्यता देगा (हालांकि इसके कुछ फैसलों को चुनौती भी दी जाएगी)। लेकिन मतदान खत्म होने पर समूचे देश को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अहसास दिलाने के लिए यह विश्वसनीयता जरूरी होगी कि क्या चुनाव आयोग महज एक संगठन की तरह चुनावों का संचालन करता रहा या यह एक ऐसा संस्थान रहा जिसने मतदाताओं को अपने भाग्यविधाता के बारे में फैसला करने लायक चुनावी प्रक्रिया के संचालन का पुनीत पवित्र कार्य पूरा किया? उच्चतम न्यायालय को सिर्फ ऐसे संगठन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जहां विवादों पर अंतिम एवं आखिरी अपील पर सुनवाई की जाती है। इसके बजाय उसे ऐसे संस्थान के रूप में दिखाई देना चाहिए जो इंसाफ देने के पुनीत कार्य का संचालन कर रहा है।

(लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानाफूसी

फरार प्रत्याशी

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को घोसी में एक संयुक्त सभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को एक साथ संबोधित किया है लेकिन इस रैली में खास बात यह थी कि प्रत्याशी अतुल राय स्वयं नदारद थे। राय यहां बसपा के प्रत्याशी हैं। दरअसल वह पिछली 1 मई से फरार हैं। एक कॉलेज छात्रा ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस की बात पर यकीन करें तो राय के किसी दूसरे मुल्क भाग जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया है। बहरहाल राय की गिरफ्तारी की आशंका के बीच दोनों नेताओं ने अपने-अपने दलों के समर्थकों से उन्हें वोट करने को कहा। विदित हो कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा।

केबल का बिल

तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम और कांग्रेस गठबंधन राज्य सरकार पर हमला करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा है। आगामी 19 मई को वहां चार विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस गठबंधन के नेता केबल का बिल सस्ता करने की बात कहकर अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। शिवगंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदंबरम ने सबसे पहले अपनी रैली में आई महिलाओं से वादा किया कि अगर वे गठबंधन को जिताती हैं तो उनको अपने पसंदीदा सीरियल देखने के लिए अधिक खर्च नहीं करना होगा। द्रमुक के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने भी उपचुनाव के प्रचार में यही वादा किया। उन्हें लगा कि उनका भाषण सुनने आई महिलाओं को शायद अपने पसंदीदा सीरियल छोड़कर आना पड़ा होगा, इसलिए उन्होंने पूछा कि वे अभी केबल के लिए कितने पैसे दे रही हैं। 300 रुपये शुल्क सुनने के बाद उन्होंने कहा कि द्रमुक के कार्यकाल में यह 100 रुपये मासिक हुआ करता था और सत्ता में आने के बाद पार्टी दोबारा इसे घटाकर 100 रुपये कर देगी।

आपका पक्ष

पानी की बूंद-बूंद बचाना जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। अभी देश में सातवें चरण का मतदान बाकी है, लेकिन राजनेता अपने भाषण में बुनियादी समस्याओं का जिक्र करना उचित नहीं समझते हैं। एक गैर सरकारी संगठन के अनुसार दुनिया में भूमिगत जल तेजी से खत्म हो रहा है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच वैश्विक भूजल में 22 फीसदी की कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग करता है और यहां भूजल में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। नीति आयोग द्वारा पिछले वर्ष जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार भारत में 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। विश्व में 90 प्रतिशत बीमारी पानी के कारण होती है। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं होता है। पानी की समस्या का संबंध सिर्फ किसी विशेष मौसम से नहीं है और

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पानी भरने के लिए डिब्बों की लगी लंबी कतार *-पीटीआई*

न ही दिए गए आंकड़ों से है। यह वह स्थिति है जिसमें दिन प्रतिदिन पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। अब जहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर बारिश के पानी का हमारे यहां प्रबंधन भी नहीं है। इसके साथ ही अनावश्यक खनन ने भूमिगत जल की स्थिति को संकट में डाल दिया है। बॉक्साइट जैसे खनिजों की विशेषता होती है कि यह भूजल स्तर को गिरने से रोकती है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से इसकी मांग बढ़ी है उससे इसका अत्याधिक खनन हो रहा है। ऐसी और भी कई वजह हैं जिसने पानी की समस्या को बढ़ा दिया है। लातूर, बुंदेलखंड और विदर्भ में पानी के संकट की जो स्थिति है, वह आने वाले दिनों में व्यापक रूप धारण कर सकती है। देश में वंचित समुदाय और निम्न वर्गों तक जीवन की बुनियादी जरूरतों की पहुंच नहीं है, उनमें से एक पानी भी है। प्रशासन और समाज का संपन्न तबका इन वर्गों की लगातार अनदेखी करता रहा है। ऐसे में लोगों के बीच पानी की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से जागरूक करना होगा, क्योंकि पानी की एक-एक बूंद को बचाने में जनभागीदारी जरूरी है।

दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर

नेताओं के बयानों में भाषा का स्तर

लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर का मतदान शेष रह गया है। लेकिन नेताओं के बयान में भाषा स्तर गिरते जा रहा है। हाल में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने 1984 सिख दंगों पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बयान की निंदा की। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने तमिलनाडु में गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी कह कर विवाद को जन्म दे दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में थप्पड़ मारने की बात कह डाली। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय पर टिप्पणी कर दी। भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले में विपक्षी उम्मीदवार के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा पर ओछी टिप्पणी की। नेताओं के बयान से समाज पर असर पड़ने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत संदेश पहुंचेगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।